

दिल्ली के कालकाजी में 16 वर्षीय छात्र की वाकू मारकर हत्या, स्कूल से लौटते समय हुआ हमला

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कालकाजी इलाके में सोमवार दोपहर करीब 2 बजे एक 16 वर्षीय स्कूल छात्र की वाकू मारकर हत्या कर दी गई। सनसनीखेज हत्या की खबरों ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार छात्र स्कूल से घर लौट रहा था, तभी उस पर वाकू से हमला किया गया। हमले में गंभीर रूप से घायल छात्र की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके पर खुद डीसीपी साउथ ईस्ट हेमंत विवारी भी पहुंचे। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है तथा प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है।

बहुजन हिताय!



बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्दजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat.net, E-mail: saksham.bharat@hotmail.com

Member: CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 249 ● नई दिल्ली ● बुधवार 22 जुलाई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन

मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail: rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती प्रबन्धी

को-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

छात्रों की मांगें पहले से पता थीं तो लाठीचार्ज का इंतजार क्यों? नड्डा के बयान पर सिब्बल ने उठाए सवाल

नई दिल्ली। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के उस बयान की आलोचना की, जिसमें उन्होंने कहा था कि पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार को बातचीत का प्रस्ताव मिला। सिब्बल ने सवाल किया कि जब "अनशन कर रहे हमारे बच्चों की मांगें" सभी को पता थीं, तो क्या सरकार उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ने और लाठीचार्ज करने का इंतजार कर रही थी। हजारों प्रदर्शनकारियों द्वारा संसद की ओर मार्च करने की कोशिश और पुलिस द्वारा उन्हें रोकने के बाद केंद्र सरकार और प्रदर्शनरत काँग्रेस जनता पार्टी (काँजपा) के बीच सोमवार को पहली प्रत्यक्ष वार्ता हुई। इस दौरान नड्डा ने संगठन के दो प्रतिनिधियों से मुलाकात की। नड्डा ने प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि सरकार का शीर्ष नेतृत्व उनकी मांगों पर आंतरिक स्तर पर विचार करेगा। काँजपा के अनुसार, यह आश्वासन तब मिला जब उसके प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरभ दास ने नड्डा से उनके आवास पर दो घंटे के भीतर दो बार मुलाकात की। संगठन का कहना है कि नड्डा ने सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उनसे बातचीत की। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए सिब्बल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, "नड्डा (ने कहा): प्रदर्शनकारियों की तरफ से पहली बार सरकार को बातचीत का प्रस्ताव आया। कितना अहंकार है।" निर्दलीय राज्यसभा सदस्य ने लिखा, "अनशन कर रहे हमारे बच्चों की मांगें सभी को पता थीं। सरकार क्या कर रही थी? क्या वह सिर्फ देख रही थी और उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ने तथा लाठीचार्ज करने का इंतजार कर रही थी? यह शर्मनाक है।" सरकार और युवाओं के नेतृत्व वाले काँजपा के बीच यह पहला सीधा संपर्क उस दिन हुआ, जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को संसद की ओर मार्च करने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया।

दिल्ली प्रोटेस्ट में घायल बच्चों की मदद के लिए केजरीवाल का बड़ा ऐलान, मेडिकल और लीगल हेल्प का वादा

नई दिल्ली। हिंसक झड़पों के बाद दिल्ली पुलिस को जंतर-मंतर खाली करना पड़ा था, लेकिन उसके अगले ही दिन, यानी सोमवार देर रात 'काँग्रेस जनता पार्टी' के सदस्य विरोध स्थल पर लौट आए और राजधानी में अपना आंदोलन फिर से शुरू कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की इजाजत तो दी, लेकिन सुरक्षा काफी बढ़ दी गई है क्योंकि आशंका है कि प्रदर्शनकारी एक बार फिर संसद की ओर मार्च करने की कोशिश कर सकते हैं। यह नया विरोध प्रदर्शन सोमवार को हुई हिंसा के बाद हो रहा है, जिसमें 100 से ज्यादा पुलिस और पैरामिलिट्री जवान घायल हो गए थे और हंगामा करने वालों के खिलाफ कई सट्टकदर्ज की गई थीं। पुलिस के मुताबिक, दिन भर चली हिंसा के बाद इलाके को खाली कराए जाने के बाद सोमवार देर रात प्रदर्शनकारी फिर से जंतर-मंतर पर जुटने लगे। अधिकारियों ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को इकट्ठा



होने से नहीं रोका जाएगा, लेकिन चेतावनी दी कि कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा करने की किसी भी कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालात को काबू में रखने के लिए विरोध स्थल और उसके आसपास सुरक्षाकर्मियों की भारी तैनाती की गई है। पुलिस ने बताया कि करीब 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। काँग्रेस जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव

दास ने कहा कि उन्होंने नड्डा के सामने तीन मांगें रखीं, जिनमें शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा और नीट की तैयारी करने वाले उन छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देना शामिल है, जिनमें से 20 से ज्यादा छात्रों की जान चली गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी ने एक हेल्पलाइन नंबर 8588833548 शुरू किया है। इसका मकसद घायल

प्रदर्शनकारियों को मेडिकल मदद देना और हिरासत में लिए गए छात्रों के परिवारों को कानूनी सहायता पहुंचाना है। केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि युवा प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता हमने देखी। मोदी सरकार ने हमारे बच्चों के साथ जैसा बर्ताव किया, वैसा तो अंग्रेजों ने भी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ नहीं किया था। वीडियो में दिखा कि पुलिस ने बिना किसी उकसावे के लड़कियों और छात्रों को पीटा और उन पर लाठीचार्ज किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। वे उन लोगों से मिलने गए थे जो एक दिन पहले सीजेपी प्रोटेस्ट मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई में घायल हो गए थे। यह दौर राहुल गांधी द्वारा आज सरकार की कड़ी आलोचना के बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई के लिए केंद्र के रवैये को बेहद अहंकारी बताया था।

'अस्पताल इलाज का केंद्र है, हिरासत का नहीं'; सफदरजंग रेजिडेंट डॉक्टरों ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी

नई दिल्ली। सोनम वांगचुक प्रकरण को लेकर वीएमएमसी एवं सफदरजंग अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों एसोसिएशन (आरडीए) ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अस्पताल की स्वायत्तता, मरीजों के अधिकार और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप की मांग की है। डॉक्टरों का कहना है कि वांगचुक की भर्ती के दौरान अस्पताल परिसर में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई, कई हिस्सों को सील कर दिया गया और इससे सामान्य मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुईं। पत्र में कहा गया है कि यदि कोई सक्षम मरीज लीव अग्रेस्ट मेडिकल एडवाइस (एलएएमए) लेकर अस्पताल छोड़ना चाहता है और उसे इसकी अनुमति नहीं दी जाती, तो यह उसकी स्वायत्तता और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। डॉक्टरों ने

कहा कि सरकारी अस्पताल उपचार के लिए होते हैं, उन्हें कानून प्रवर्तन एजेंसियों के विस्तार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अस्पताल प्रशासन को किसी भी गैर-चिकित्सकीय दबाव से मुक्त रखा जाना चाहिए। रेजिडेंट डॉक्टरों ने जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की भी निंदा की। पत्र में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी सदस्यों और छात्रों के साथ कथित दुर्व्यवहार का उल्लेख करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों और संवैधानिक स्वतंत्रताओं के विपरीत बताया गया है। आरडीए ने राष्ट्रपति से पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच, सक्षम मरीजों के एलएएमए अधिकार की रक्षा, अस्पतालों को केवल स्वास्थ्य

सेवाओं तक सीमित रखने, सफदरजंग अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तथा स्वास्थ्यकर्मियों, छात्रों और शांतिपूर्ण नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष डॉ. देवांशी कौल, उपाध्यक्ष डॉ. राहुल, महासचिव डॉ. आयुष राज, संयुक्त सचिव डॉ. अमित यादव और कोषाध्यक्ष डॉ. रोहित राठी ने हस्ताक्षर कर कहा कि यह पत्र किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि मेडिकल एथिक्स, मरीजों के अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए लिखा गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन मुद्दों पर शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया तो स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं और डॉक्टरों में असंतोष बढ़ सकता है।

राज्यसभा में मेरा माईक बंद कर दिया गया, सीजेपी विरोध प्रदर्शन पर मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र पर गंभीर आरोप

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को राजधानी में सीजेपी विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई की आलोचना की और आरोप लगाया कि विपक्ष को संसद में यह मुद्दा उठाने नहीं दिया गया। पत्रकारों से बात करते हुए खड़गे ने आरोप लगाया कि पेपर लीक के कथित मामले को लेकर सीजेपी विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों पर पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। खड़गे ने कहा लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़ी गई और छात्रों की पिटाई की गई, जिससे कई लोग अस्पताल पहुंच गए। इस अन्याय, दमन और उन पर डाले जा रहे दबाव के खिलाफ, हमने उनकी ओर से आवाज उठाने के लिए संसद में समय मांगा था। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने यह मुद्दा उठाने की कोशिश की, तो उन्हें राज्यसभा में बोलने से रोका गया। उन्होंने कहा कि लेकिन जैसे ही मैं खड़ा हुआ और एक शब्द भी बोला, माईक बंद कर दिया गया। क्या यही लोकतंत्र है? अगर लोकतंत्र में आप बहस नहीं करना चाहते या हमारी बात नहीं सुनना चाहते, तो हम कहीं जाएं? देश के हर कोने से लाखों छात्र अपनी आवाज पहुंचाने के लिए आए हैं। खड़गे ने इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की विपक्ष की मांग दोहराई



और कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस बहस का जवाब देना चाहिए। हम इस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। चर्चा के बाद, गृह मंत्री को बयान देना चाहिए। दूसरे प्लोर लीडर्स को भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए खड़गे ने कहा, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश चल रही है। यह अभूतपूर्व है - पिछले 60 सालों में मैंने किसी सरकार को इस तरह काम करते नहीं देखा। हम बस यही चाहते हैं कि चर्चा का मौका दिया जाए।

सिंधु बॉर्डर पर तलाशी अभियान

किसानों के दिल्ली कूच को लेकर दिल्ली पुलिस हार्ड अलर्ट पर है। दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस की तरफ से की गई विशेष तैयारी की गई है। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस सघन तलाशी अभियान चला रही है। बॉर्डर पर पुलिस बल के अलावा वाटर कैनन और वज्र वाहन को तैनात किया गया है। पुलिस वाहनों की तलाशी लेकर दिल्ली की ओर आ रहे किसानों को रोक रहे हैं। साथ ही तलाशी के बाद ही वाहनों को दिल्ली में घुसने की इजाजत दी जा रही है।

अनशन पर हैं सोनम वांगचुक, हमें कोर्ट के लिखित आदेश का इन्तजार: गीतांजलि आंगमो

नई दिल्ली। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि आंगमो ने कहा कि मैं इस मामले को सही ढंग से सुलझाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का शुक्रिया अदा करती हूँ। भारत में एक लोकतांत्रिक नागरिक को अपनी पसंद का डॉक्टर, अस्पताल और इलाज चुनने का अधिकार है। यहाँ उन्हें जिस तरह से लाया गया था, उसके कारण हमें भरोसा नहीं हो रहा था। उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी सेहत की निगरानी जंतर-मंतर पर भी की जा सकती थी। यह एक तरह की नजरबंदी जैसा था ताकि वह बाहर के लोगों से संपर्क न कर सकें। उनकी सेहत से जुड़ी बातें जानलेवा नहीं हैं। सरकार से ज्यादा चिंता हमें उनकी सेहत की है। सोनम ने अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया है, ताकि वे उन छात्रों के साथ एकजुटता दिखा सकें जिनकी कल पिटाई हुई थी। सफदरजंग अस्पताल आए कई सांसदों को उनसे मिलने नहीं दिया गया। डॉ. लांबा और डॉ. दिघे, जो पिछले 20 दिनों से उनका इलाज कर रहे थे, ने आज कोर्ट को बताया कि इलाज करने वाले डॉक्टर को भी मरीज से मिलने नहीं दिया जा रहा था। हमें उस अस्पताल में नजरबंदी और कैद जैसा महसूस हुआ। लंच के बाद एक लिखित आदेश दिया जाएगा, फिर हम उन्हें मेदांता ले जाएंगे।

'यूहें ने कुतरा कंप्यूटर का तार तो कर्मचारी की जेब होगी ढीली', राऊज एवेन्यू कोर्ट का आदेश

नई दिल्ली। राऊज एवेन्यू स्थित जिला अदालत में अब चूँचूँ और काकरोचों की शरारत भी कर्मचारियों की जेब पर भारी पड़ सकती है। कोर्ट प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यदि कार्यालय में लापरवाही के कारण सरकारी कंप्यूटर या अन्य हार्डवेयर चूँचूँ, काकरोचों या चाय-काफी जैसे पेय पदार्थ गिरने से खराब होता है, तो उसकी मरम्मत का खर्च संबंधित कर्मचारी को ही उठाना होगा। कंप्यूटर शाखा के प्रभारी एवं विशेष न्यायाधीश अतुल कृष्ण अग्रवाल ने आदेश जारी कर कहा कि हल के दिनों में कई कंप्यूटर ऐसी वजहों से खराब हुए, जिन्हें थोड़े सावधानी से रोका जा सकता था। जांच में सामने आया कि कार्यालयों में छोड़ा गया खाने-पीने का कचरा चूँचूँ और काकरोचों को आकर्षित कर रहा है। ये कंप्यूटर के अंदर घुसकर तारों और अन्य संवेदनशील पुर्जों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहाँ, कई मामलों में चाय, कॉफी या पानी गिरने से भी सिस्टम खराब हुए। आदेश में कहा गया कि कोर्ट रूम, अहलमद कक्ष, पेंटी और अन्य शाखाओं में खड़े डस्टबिन में खाने का बचा सामान, पैपर, फायल पैपर या अन्य खाद्य सामग्री नहीं डाली जाएगी।

निर्यात हब

किम्हीं भी राज्य की आर्थिक प्रगति केवल उत्पादन बढ़ाने से नहीं, बल्कि उसके उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने की क्षमता से निर्धारित होती है। आज वैश्विक अर्थव्यवस्था के इस प्रतिस्पर्धी दौर में वही राज्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने उद्योग, कृषि, निवेश और निर्यात को एकीकृत विकास मॉडल के रूप में अपनाया है। उत्तर प्रदेश भी इसी दिशा में निरंतर नए अवसर स्रष्टाित कर रहा है। मुहूर्तमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास, निवेश और निर्यात को नई गति देने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक तीन वर्षों के लिए पुष्कट आकर्षकारी निर्यात नीति लागू करने का फैसला किया है। इस दूरदर्शी फैल के साथ उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने पहली बार तीन वर्षीय अलग आकर्षारी निर्यात नीति लागू की है। यह नीति केवल आकर्षारी उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि कृषि, उद्योग, निवेश, रोजगार और वैश्विक व्यापार को एक साझा विकास दृष्टि से जोड़ने वाली व्यापक आर्थिक रणनीति है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में निर्मित उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप तैयार करना, निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी वातावरण उपलब्ध करना तथा प्रदेश की वैश्विक निर्यात मार्गचित्र पर मजबूत पहचान दिलाना है। उत्तर प्रदेश अब अल्पकालिक प्रशासनिक उपायों से आगे बढ़कर दीर्घकालिक आर्थिक नियोजन की दिशा में प्रगाढ़ी कदम उठा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने औद्योगिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। बेहतर कानून-व्यवस्था, निवेशक-अनुकूल नीतियां, विश्वस्तरीय एलएमएम-वे डेवल्प्मेंट, आधुनिक लॉजिस्टिक्स, मिमल बिंदो प्रणाली तथा 'इन ऑफ़डूटिंग बिजनेस' में सुधार ने प्रदेश को निवेश का परसिद्ध गंतव्य बनाया है। अब सरकार का लक्ष्य इन औद्योगिक उपलब्धियों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाना है। नई आकर्षारी निर्यात नीति इसी व्यापक सोच का परिणाम है, जो उत्तर प्रदेश को एक मजबूत विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुहूर्तमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की यह नीति कृषि और उद्योग के बीच एक सशक्त आर्थिक सेतु का कार्य करेगी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। इसके साथ ही प्रदेश में बड़े पौमने पर अनाज, फल एवं अन्य कृषि उत्पादों का उत्पादन होता है। इन कृषि संसाधनों पर आधारित डिस्टिलरी, एंफेनॉल एवं संबन्धित उद्योगों को नई नीति से विशेष लाभ मिलेगा। स्थानीय स्तर पर उत्कृष्ट कच्चे माल का आर्थिक उपयोग होने से किसानों को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलेगा, कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन होगा तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्राप्त होगी। यह नीति केवल उद्योगों को ही नहीं, बल्कि लाखों किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होगी। इस नीति के तहत निर्यात को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण नियामतें प्रदान की हैं। नई नीति के अंतर्गत निर्यातिर उपायन शुभ्मत के 25 प्रतिशत तक के समस्तुय निर्यात के लिए उपयोग करने वाले निर्यातकों हेतु बेहतर भाई शुल्क, निर्यात फस शुल्क, फ्रेइटवनी शुल्क तथा स्पेशल पैस को दरी को न्यूनतम स्तर तक कम कर दिया है। इससे निर्यात लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी और उत्तर प्रदेश में निर्मित उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। साथ ही ब्रांड पंजीकरण एवं लेबल अनुमोदन की प्रक्रिया को भी सरल और पारदर्शी बनाया गया है, जिससे उद्योगों का समय और लागत दोनों बचेगें तथा व्यापारिक गतिविधियों की गति मिलेगी। नई आबकारी निर्यात नीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राक्धान शीरा आधारित एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (एनए) के अंतर्राष्ट्रीय निर्यात में संबंधित है। प्रदेश सरकार ने इस पर लागने वाले शुल्क को ध्वस्त मात्र 50 पैसे प्रति बल्क लीटर तक कम कर दिया है। यह निर्णय प्रदेश की डिस्टिलरी इकाइयों के लिए अत्यंत लाभकारी साबिन होगा। इससे उत्तर प्रदेश में निर्मित इथेनॉल अन्य राज्यों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उपलब्ध होगा और राज्य की औद्योगिक इकाइयों की बाजार हिस्सेदारी बढ़ने को सहायनाएँ और आर्थिक मजबूती होगी। सरकार ने इस नीति में केवल निर्यात बढ़ाने पर ही ध्यान केंद्रित नहीं किया है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय पहचान को भी वैश्विक मंच तक पहुंचाने का प्रयास किया है। नीति के अंतर्गत डिस्टेंट मॉडरन के निर्माण, टैगिस्ट टेवर्न तथा फूडकर बिस्को की अनुमति का प्राक्धान किया गया है। यह फैल प्रदेश की पारंपरिक उत्पाद संस्कृति को नई पहचान प्रदान करेगा। विश्व के अनेक देशों में स्थानीय पेय उत्पाद वहाँ की सांस्कृतिक पहचान और परंपरा का महत्वपूर्ण अभिन्न होते हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश भी अपनी ऐतिहासिक विरासत और स्थानीय उत्पादों को आर्थिक अक्सर में परिचित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहा है। नई आकर्षारी निर्यात नीति का प्रभाव केवल डिस्टिलरी उद्योग तक सीमित नहीं रहेगा। जैसे-जैसे निर्यात गतिविधियां बढ़ेंगी, जैसे-जैसे पैकेजिंग उद्योग, परिवहन सेवाएं, वेयरहाउसिंग, कोल्ट चेंजे, कंटेनर लॉजिस्टिक्स, निर्यात आनुवंशि शुक्ला तथा अन्य सहायक उद्योगों में भी निवेश बढ़ेगा। इससे प्रदेश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। विविध रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों के विस्तार से स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा और युवाओं को अपने ही प्रदेश में बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी तथा पलायन में भी कमी आएगी। यह नीति निवेशकों के लिए भी दीर्घकालिक स्थिरता का संदेश देती है। तीन वर्षों की स्पष्ट नीति व्यवस्था उद्योगों को भविष्य की योजनाएं बनाने, निवेश बढ़ाने और वैश्विक बाजारों में अपनी रणनीति तैयार करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करेगी। स्थिर नीति वातावरण निवेशकों का विश्वास मजबूत करता है और प्रदेश में दीर्घकालिक औद्योगिक विकास का आधार तैयार करता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश आज देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। आज उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। आधुनिक औद्योगिक विकास, कृषि आधारित मूल संरचना, निर्यात संरचना और रोजगार सृजन को यह समर्थन रणनीति प्रदान करेगी देश की महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित कर रही है।

ईरान क्यों पहुंचा रूस का प्रलय विमान ?

ईरान को घुटनों के बल लाने के लिए अमेरिका कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहा है, चर्मा की बोझार हो रही है। ईरान भी पलटवार कर रहा है, मगर इन संर्भके बीच एक खास तरह के रूसी विमान ने तेहरान की सरजमी पर उतर कर पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। इस विमान को दुम्पडे विमान कहा जाता है। दुम्पडे का शाब्दिक अर्थ प्रलय या कयामत का दिन होता है। यह विमान खासतौर पर वेमो हैं दिन के लिए तैयार किया गया है। सबसे पहले यह समझिए कि यह दुम्पडे विमान होता क्या है? दुनिया में सीमित तौर पर अमेरिका, रूस और चीन के पास इस तरह के विमान हैं। मगर अधोचित रूप से भी कुछ और देशों के पास ऐसे विमान हो सकते हैं, यदि कहीं परमाणु हमला हो जाए तो यह विमान देश चलाने वाले नेताओं और अधिकारियों को लेकर न केवल सुरक्षित उड़ जाएगा बल्कि इन्हां में रहते हुए इन्हां में बैठे नेतृत्वका दुश्मन देश पर हमले के लिए कमांड भी दे सकते हैं। यह विमान परमाणु हमले को भी सुरक्षित तौर पर ड़ेल सकता है। सामान्य तौर पर यह विमान सात हजार किलोमीटर दूर तक सफर कर सकता है लेकिन इसमें बीच रास्ते में हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता भी है जिसके कारण यह और लंबी दूरी तय कर सकता है, तो हुआ यह कि विमानों की उड़ान पर नजर रखने वालों ने देखा कि रूस का दुम्पडे विमान 13 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमीन इंटरनैशनल एयरपोर्ट पर उतरा और कुछ घंटों के बाद चीन की राजधानी बीजिंग के लिए रवाना हो गया। अब संर्भके सामने यही गंभीर सवाल है कि उड़ान हुआ केमिलन कहा जाने वाला यह विमान ईरान क्यों पहुंचा? क्या यह किसी खास सुरक्षा बेजक के लिए पहुंचा था? क्योंकि इस रूसी विमान में खास एंस्क्रेटेड मेटलहाट लिंक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग

लगी है और अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक जासूसी यहां काम नहीं कर सकता। तो क्या तेहरान में बैठे किसी खास व्यक्ति से पुलिन को बात करनी थी? क्या यह विमान तेहरान में किसी खास व्यक्ति को लेकर उड़ा था फिर किसी खास व्यक्ति को तेहरान छोड़ने आया था? यह सवाल इसलिए क्योंकि यह बात चर्चा में थी कि अमेरिकी हमले में धायल होने के बाद मौजनाब को सुरक्षा की दृष्टि से रूस में रखा गया था, मगर ये सब बस मन में ठठने वाले सवाल हैं जिनका जवाब स्पष्ट रूप से कहीं मौजूद नहीं है लेकिन एक बात साफ है कि रूस ने दुम्पडे विमान तेहरान भेजकर साफ संकेत दे दिया है कि वह ईरान के साथ मजबूती से खड़ा है। वैसे भी दोनों देशों ने पिछले साल 20 वर्षों की व्यापक रणनीतिक सझौदारी पर हस्ताक्षर किए थे, दोनों देश मेटलहाट तस्वीरों और डाटा के साथ ही अन्य सुविधा जानकारीयां साझा कर रहे हैं। एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम और अत्याधुनिक लड़ाकू विमान भी ईरान को मिलने वाले हैं। संभव है कि मिल तो गए हों, हालांकि समझौते में ऐसा कोई प्राक्धान नहीं है कि ईरान पर हमला होने की स्थिति में रूस सीधे तौर पर युद्ध में शामिल होने के लिए बाध्य हो लेकिन इस पर कोई रोक भी नहीं है। तो सवाल है कि क्या रूस ऐसा करेगा? मुझे नहीं लगता कि रूस को सीधे जंग में शामिल होने की कोई जरूरत है, हाँ, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की पर पुलिन को नजर जरूर है। जेलेंस्की ने खाड़ी देशों की यात्राएँ की हैं और सऊदी अरब तथा कतर के साथ महत्वपूर्ण रक्षा सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए हैं, इसलिए रूस के लिए जरूरी हो गया है कि वह ईरान के माध्यम से न केवल अमेरिका बल्कि खाड़ी के देशों को डटका दे। चीन की चतुर चाल ने रचा है भाग्यनाल एक सवाल अंगूर रह गया कि प्रलय

के दिन वाता विमान तेहरान से उड़कर सीधे मास्को न लैंडने के बजाय बीजिंग क्यों गया? क्या किसी को तेहरान से बीजिंग पहुंचाने गया था? यदि हाँ, तो वह कौन था? यदि नहीं, तो फिर बीजिंग जाने की जरूरत क्या थी? तेहरान से मास्को की हवाई दूरी करीब 2500 किमी है जबकि दुम्पडे विमान ने तेहरान से बीजिंग होते हुए मास्को पहुंचने के लिए करीब 11500 किलोमीटर की उड़ान भरी। यानी कहीं न कहीं कुछ मामला तो था, फिलहाल अमेरिका भी इस विमान को लेकर मीन है। तो क्या उसे विमान का राहस्य समझ में नहीं आया? क्योंकि कुछ समझ में आया होता तो ट्रम्प साहब कहां नुप रहने वाले थे। ट्रम्प साहब खुले इंद्रव के हैं, कुछ भी छिपा कर नहीं रखते। इधर पुलिन और चीं जिनपिंग है कि कुछ बेचंते ही नहीं। सोमन वांगचुक और राजनीति का सवाल पर्यावरण और शिक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्टशन के लिए सोमन वांगचुक की जितनी तारीफ की जाए, वो कम ही होगी। उनके प्रयोगों ने लेह लक्ष्म क्षेत्र के जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने का रास्ता दिखाया है, उनकी जिंदगी देश की धरोहर है, इसलिए उन्होंने जब आमरण अनशन शुरू किया तो मेरे मन में ये सवाल उठा कि क्या उन्हें अपने सम्मान का राजनीतिक उपयोग किसी को करने देना चाहिए? आपको याद होगा कि देश की वाज्जिन समस्याओं को लेकर अन्ना हजारे ने भी अनशन किया था लेकिन वैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि उनका राजनीतिक उपयोग करने को कोशिश को ना रही है, उन्होंने बहुत को अलग कर लिया था। मुझे लगता है कि सोमन वांगचुक को ज्यादा जरूरत पर्यावरण और शिक्षा को है, ईंधन से प्रार्थना कर रहा हूं कि वे स्वस्थ और सक्रिय रहें। राजनीति के शिकार न बनें।

‘हिंदुस्तान के हिस्से का बिल’ भी भर रहा है पाकिस्तान!

सीमापार आतंकवाद को अपनी सत्कारी नीति बना चुके पाकिस्तान की आन ऐसी दुर्गति हो चुकी है कि वह भारत के खिलाफ ग्यानिश रचने की कीमत भी अपनी जेब से चुका रहा है। दरअसल, सिंधु जल संधि को लेकर भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर घेरने की नाकाम कोशिश में इसमाभावद न केवल अपनी ओर से खर्च उठा रहा है, बल्कि भारत के हिस्से का व्यय भी खुद अंदा कर रहा है। यानी जिस देश को वह कंठधरे में खड़ा करना चाहता है, उसी का बिल भी उसे भरना पड़ रहा है। यह दृश्य पाकिस्तान की आर्थिक बदहली, कुटनीतिक बेवसी और बेवस्ताहट का सबसे बड़ा प्रमाण है। दुनिया के सामने भारत को घेरने फिलहा पाकिस्तान आज अपनी ही बनई चूल्ह में फंसेकर उपहास का पात्र बन गया है। हम आपको बता दें कि सिंधु जल संधि वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत छह नदीयों के जल के बंटवारे का डंका तय किया गया था। दशकों तक भारत ने संधि का पूरी निष्ठा से पालन किया, जबकि दूसरी ओर पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को संरक्षण देता रहा। फलश्रुति में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत ने स्पष्ट संदेश दिया कि जब तक पाकिस्तान सीमापार आतंकवाद का निरन्तरनीय और स्थयी रूप से परित्याग नहीं करता, तब तक सामान्य स्थिति की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसी क्रम में भारत ने संधि से जुड़ी कार्यवाहियों में अपनी भागीदारी स्थगित कर दी। भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। नई दिल्ली का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियां 1960 उसी नहीं रही। जलवायु परिवर्तन, बृक्षों आबादी, ऊर्मा की आवश्यकता, नई प्रौद्योगिकी और सबसे बढ़कर पाकिस्तान प्रायोजित योगापार आतंकवाद ने पूरे परिदृश्य को बदल दिया है। ऐसे में संधि की समीक्षा और नए सिरे से विचार स्वाभाविक आवश्यकता है। इसके विपरीत पाकिस्तान हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत को घेरने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन विडम्वना देखिए कि जिस माध्यमस्था प्रक्रिया से वह भारत पर दबाव बनाता चाहता है, उसी का पूरा आर्थिक बोझ भी उसे स्वयं उठाना पड़ रहा है। यह उस कुटनीतिक दिवालियेपन का प्रतीक है जिसमें पाकिस्तान दुनिया के सामने अपनी इतनी जीवित रखने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार दिखाई देता है। सच्चाई यह भी है कि सिंधु जल संधि से दशकों तक सबसे बड़ा लाभ पाकिस्तान को मिला। भारत, ऊपरी प्रवाह वाला देश होने के बावजूद, संधि की कंठरी शर्तों का पालन करता रहा। अनेक विशेषज्ञ लंबे समय से यह प्रश्न उठाते रहे हैं कि वह व्यवस्था भारत के हितों के अनुरूप नहीं रही। इसके बावजूद भारत ने निरंतरतए राष्ट्र का परिचय दिया। लेकिन जब पड़ोसी देश आतंकवादियों को शरण दे, प्रशिक्षण दे और भारत के निर्दोष नागरिकों का खत बहाने वालों को संरक्षण प्रदान करे, तब केवल सद्भावना के आधार पर धन्ये नहीं चल सकते। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर शीर मचाने से वास्तविकता नहीं बदलती। आतंकवाद और बातचीत, आतंकवाद और सहयोग, आतंकवाद और निरवसा, ये तीनों एक साथ नहीं चल सकते। यदि इलामाबाद वह सोचता है कि वह एक ओर आतंकियों को पालता देश और दूसरी ओर जल समझौते तथा वैश्विक संस्थाओं की आड़ लेकर भारत पर दबाव बनाएगा, तो वह उसकी सबसे बड़ी भूल है। भारत ने बार-बार संयम दिखाया है, लेकिन संयम को कमजोरी समझना पाकिस्तान की पुणनी आदत रही है।

विकसित भारत के निर्माण में कदम बढ़ाती बागपत की युवा शक्ति

भारत को वर्ष 2047 तक एक पूर्ण विकासित, आत्मनिर्भर और ज्ञान-आधारित वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में देश की युवा आबादी को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना केंद्र व प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इस राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत युवाओं को आधुनिक कोशल, उन्नत तकनीक और रोजगार के नए अवसरों से जोड़ने के लिए व्यापक स्तर पर पहल की जा रही है। 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए देश के शैक्षणिक व कोशल ढांचे को उद्योग जगत की भावों नस्लों के अनुकूल खला जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कोशल विकास अभियानों के एकीकृत समन्वय से युवाओं की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। सरकार का मुख्य उद्देश्य केवल पारंपरिक प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि युवाओं में डिजिटल सक्षमता और तकनीकी दक्षता को इस स्तर तक बढ़ाना है कि वे वैश्विक पटल पर प्रतिस्पर्धी बन सकें। देश के सूरदायक के क्षेत्रों तक उन्नत संशोधन प्रशिक्षण पहुंचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और आधुनिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का नेतृी व कारगरूप किया जा रहा है। विकसित भारत के लक्ष्य को जमीनी स्तर पर उतारने की दिशा में कोशल विकास एवं उद्योगीक मंत्रालय द्वारा जिला संशोधन कोशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट संचालित किए जा रहे हैं। इस राष्ट्रीय पहल के तहत उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद का चयन एक ऐतिहासिक और अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। देश के केवल दो चुनिंदा जनपदों में बागपत का चयन होना यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि

यहाँ की युवा क्षमता, सामाजिक ऊर्जा और विकास की अपार संभावनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर गंभीरता से स्वीकार किया गया है। बागपत जनपद में लगभग 4 लाख 70 हजार युवाओं की विशाल आबादी निवास करती है, जो हमें देश की सबसे बड़ी जनसांख्यिकी शक्ति है। यहाँ के युवा कृषि, खेल, नवचार, सामाजिक क्षेत्र और स्वरोजगार के क्षेत्र में निरंतर नई पहचान बना रहे हैं। इस पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से बागपत के युवाओं को राष्ट्रीय विकास की पुष्तापराय से जोड़कर रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यहाँ विकसित होने वाला कोशल आधारित विकास मॉडल युवाओं के उन्नत भविष्य की नई दिशा तय करेगा। वर्तमान समय में सबसे बड़ी व्यावसायिक चुनौती सृचना और अवसरों के बीच का अंतर है। बढ़ते संख्या में युवाओं को वह जानकारी हो नहीं हो पाती कि उनके लिए कौन-कौन सी योजनाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम, डिजिटल अवसर और रोजगार आधारित पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इस इन्फॉर्मेशन गैप को समाप्त करने तथा युवाओं तक एक्सेसुक्त रूप से जानकारी पहुंचाने के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा रहा है। जिला प्रशासन, कोशल विकास, शिक्षा, उद्योग, युवा कल्याण, सेवायोजना और 'माय भारत' जैसे सभी संबन्धित प्लेटफॉर्मों की एकीकृत कार्ययोजना क्रियान्वित की जा रही है। आज का युग केवल कार्पासिक डिशि आधारित शिक्षा का नहीं, बल्कि 'हिम्माट ड्रिवन रिकलिंग' यानी मांग आधारित कोशल विकास का है। युवाओं को वहीं प्रशिक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक है जिसकी वास्तविक आवश्यकता उद्योगों और आधुनिक रोजगार बाजार में है। इसके लिए बागपत जनपद में संचालित उद्योगों, कर्मियों,

व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और उपरते रोजगार क्षेत्रों की जरूरतों का विमर्तुत सवे और वैज्ञानिक आकलन कर उद्योगों को अनुरूप नए पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए जा रहे हैं। बागपत एक समृद्ध कृषि प्रधान क्षेत्र होने के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से भी सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। इस भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जनपद में पृष्ट प्रोप्रेटियर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एसी बिजनेस, तकनीकी सेवाएं, ई-कॉमर्स और स्वरोजगार आधारित कोशल विकास की व्यापक संभावनाएं चिन्हित की गई हैं। इन उपरते क्षेत्रों में युवाओं को व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित कर उन्हें न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार से जोड़ा जा रहा है, बल्कि स्व-उपमोता के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। वर्तमान समय में शिक्षा और रोजगार के बीच बढ़ती दूरी को समाप्त करने के लिए व्यापक स्तर पर 'सिकल मैपिंग' को ना रही है। इसके तहत युवाओं की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म, डेटा एनालिटिक्स और नई तकनीकों के दौर में 'फ्युचर रेडी' बनाया जा रहा है। ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाकर वैश्विक पटल पर प्रतिस्पर्धी बनाने का प्रयास निरंतर जारी है। इस पूरी प्रक्रिया में निपुण भारत मिशन और अपार काहें जैसी राष्ट्रीय पहलों को भी आधारभूत संबल के रूप में जोड़ा जा रहा है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर 'रोजगार प्रताप' बनाने के दृष्टिकोण से 'स्टार्टअप इंडिया' और 'स्टैंडअप इंडिया' जैसी महावाकंशी योजनाओं को कोशल विकास कार्यक्रमों से सीधे एकीकृत किया जा रहा है। इसके माध्यम से नवोपेमा विचारों वाले युवाओं को निवेश सहायक, मेगटोरिप और इन्क्यूबेशन सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जिससे बागपत में नवचार और

स्टार्टअप संस्कृति का एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो सके। स्थानीय स्तर पर योजनाओं की जानकारी अतिम युवा तक पहुंचाने के लिए 'यूथ कनेक्टिविटी' के रूप में डज्जालन युवाओं की पहचान की जा रही है। गांवों, कस्बा, कॉलेजों, स्वयंसेवी मण्डलों और युवा समूहों के माध्यम से युवाओं को इस मिशन मोड अभियान से सक्रिय रूप से जोड़ा जा रहा है। विकसित भारत मिशन के अंतर्गत युवाओं की भूमिका केवल किसी योजना के लापशील तक सीमित न रहकर उन्नत विकास प्रक्रिया का नेतृत्वकर्ता और परिवर्तन वाहक बनाया जा रहा है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी (पब्लिक् मॉडल) को बढ़ावा देते हुए औद्योगिक संस्थानों, तकनीकी संस्थानों और उद्योग क्षेत्रों के दिग्गजों को एक मंच पर लाया जा रहा है। इससे युवाओं के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण, ऑन-द-जीब ट्रेनिंग और इंटर्नीप के नए मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं। वह रणनीतिक तालमेल युवाओं के अकादमिक ज्ञान और उद्योग जगत की वास्तविक व्यावहारिक जरूरतों के बीच मौजूद अंतर को पूरी तरह समाप्त करने में मील का पत्थर साबित हो रहा है। बागपत में क्रियान्वित किया जा रहा यह पाथलट प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्तर पर एक अनुकरणीय और परिणामरूप मॉडल प्रस्तुत करेगा। जनघातदारी पर आधारित इस अभियान से हजारों युवा सीधे तौर पर लाभान्वित होकर विभिन्न आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में अपना योगदान देंगे। बागपत में विकसित होने वाला यह सफल मॉडल भविष्य में देश के अन्य जनपदों में भी लागू किया जा सकेगा। कोशलयुक्त, डिजिटल रूप से सक्षम और तकनीकी रूप से निपुण युवा ही वर्ष 2047 तक भारत को एक पूर्ण विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर महाशक्ति बनाने की सबसे मजबूत नीति साबित होंगे।

छात्र आंदोलनों, अयोध्या मंदिर दान प्रकरण तथा परिसीमन जैसे विषयों पर घरेलू शुरु

वैश्विक स्तरपर 20 जुलाई 2026 से प्रारंभ हुआ 13 अगस्त तक चलने वाले इस संसद के मासूम सत्र पर पूरे विश्व की नजरे लगी हुई है।साल 19 अक्टू के निर्धारित है।संसद में 28 विधेयक लंबित है।इसमें से 5 नए विधेयक पेश किए जाने हैं और 2 लंबित विधेयकों को पारित करने के लिए मूचीबद्ध किया गया है।हाल केवल एक निर्णय संसदीय सत्र नहीं,बल्कि भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था निवेश वातावरण और वैश्विक छवि के लिए एक फलवली प्रोत्सा माना जा रहा है। यह सत्र ऐसे समय शुरू हुआ है जब भारत दुनियाँ की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है,भारत-विदेश मुक्त व्यापार समझौता लागू हो चुका है,अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की निगाह भारत पर है और विकसित भारत -2047 का गेटवेज निर्माणक चरण में प्रवेश कर रहा है।मैं एउकेकेड किशन समसुखदस भावनाजी गोरिया महाशय्ठ अपने विचार इस आडिंकल के माध्यम से प्रकट कर रहा हूँ कि ऐसे समय संसद में होने वाली प्रत्येक बहस, प्रत्येक विधेयक और प्रत्येक राजनीतिक टकराव का प्रभाव केवल नई दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा,बल्कि वैश्विक निवेशकों, अंतरराष्ट्रीय निवेश संस्थाओं और भारतीय शैर्य बाजार पर भी दिखाई देगा।मगर प्राथम होने से पहले माननीय पीएम ने संसद परिसर में गौडिछा को संबोधित करते हुए सभी दलों से रचनात्मक सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा

कि संसद का उपायक संचालन देशहित,जनकल्याण और विकास के लिए आवश्यक है तथा भारत की हल की उपलब्धियों को आगे बढ़ाने के लिए सार्वभू चर्चा जैनी चाहिए। दूसरी ओर विषय पहले से ही संसद को कई मुद्दों पर घेने की रणनीति बनकर आया था, जिससे पहले दिन से ही टकराव की स्थिति बन गई। साक्षियों, सरकार ने इस मनसुत सब के लिए लगभग आठ प्रमुख विधेयकों का विचार भी एजेन्ड रखा है। इनमें इकम-टैक्स (अमेन्डमेंट) बिल,2026,जिसमें विदेशी संस्थागत निवेशकों और बैंक फंड इंटरनेशनल मेटलमैट्स को समक्षी प्रतिभूमियों से होने वाले आय पर कर छूट से संबंधी प्रावधानों, महकौ, प्रकल एंड मीडियम इंटरब्रैजनेन डेवलपमेंट (अमेन्डमेंट) बिल 2026 एएसएसईई को मायप पर भुगतान सुनिश्चित करने की व्यवस्था मजबूत करना। मध्यस्थता (अप्रोवियेन्स) के निर्णयों के प्राप्ती क्रियान्वयन का प्रावधान।राज्यों को पैरामिस्टेशन कडील के गठन में आर्थिक अधिकार देना। रजिस्ट्रेशन ऑफ कर्यय एंड डेथम (अमेन्डमेंट) बिल ,2026जम और मृत्यु के हिलिन्स पंक्जिल के निर्णयों को आर्थिक कंटेडर बनाना। पंजीकरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और निरन्तरनीय बनाना।सुप्रीम कोर्ट (नंबर ऑफ जजसे) अमेन्डमेंट बिल, 2026 सलीन्स नायाल्लाह में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की

संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रस्ताव। प्रेक्शन और ट्रंस्फरस टू नेशनल बैंनर (अमेन्डमेंट) बिल, 2026राष्ट्रीय सम्मान अभिनियम, 1971 में संशोधन। पिरोटों के अनुसार इसमें 'वी म्हात' को वैधानिक संरक्षण देने और उसके अर्पण को दंडनीय बनाने का प्राक्धान शामिल है। इसके अलावाकल्ले से लम्बित प्रमुख कई विधेयक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त राजनीतिक गलितारों में परिसीमन (डेलिमिटेशन) से जुड़े सम्पक्ति विधेयक पर भी व्यापक चर्चा रही,क्योंकि इसका संभव भविष्य में महत्वओं के आखण के प्रभावों क्रियान्वयन और लोकसभा सीटों के पुर्नवीर्धण से जोड़ा जा रहा है। हालांकि सरकार ने परिसीमन पर अंतिम निर्णय सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं किया।मगर भी यह विषय पूरे सत्र का मरिक्ता से रज्ज्म संकेतनीयत राजनीतिक मुद्दा बन गया। साक्षियों,उभर विषय ने पहले ही घोषण कर दी थी कि वह संसद को केवल विधेयकों पर नहीं,बल्कि महंगाई, बेरोजगारी,कृषि संकट, गौपण्य की स्थिति,नोट प्रेषण निबन्ड,अन अनेकनहीं अयोध्या मंदिर दान प्रकरण तथा परिसीमन जैसे विषयों पर प्रेषण। विषय का उत्तर यह कि जनता से जुड़े इन प्रश्नों पर पहले चर्चा होनी चाहिए, जल्दी संसद का जोर दिवाणी करीको आगे बढ़ाने पर था। यही उक्तवत पहले दिन काम काज शुरू होने के पहले प्ष्टे से ही सदन के भीतर खुलकर दिखाई दिया। 20

जुलाई की सुकल जैसे ही लोकसभा और रजसभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई,विषयी संसदी ने नोकबनी शुरू कर दी। विषय ने छत्र अंदोलनों और परीक्षा संरक्षी मुद्दों पर तत्काल चर्चा की मंग की।अध्यक्ष द्वारा बर-बार व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई,किंतु सेर- राखत जारी रहा। परिणामव्यक्त दोनों सदनों की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी। समाचारों के अनुसार दोपहर तक लोकसभा और रजसभा की कार्यवाही कम से कम पाँच बार स्थगित हुई और बाद में दोनों सदनों को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। पहले दिन कई बंद विचारों कायें नहीं हो सता। साक्षियों, पहले दिन की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि आगामी 25 दिन संसद और विषय के बीच तीव्री राजनीतिक प्रतिस्पर्धी देखने को मिलेगी।

सरकार का लक्ष्य आर्थिक सुधारों,कर प्रणाली, उद्योग,निवेश और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े विधेयकों को पारित करना है, जबकि विषय जगहिट से जुड़े मुद्दों पर संसद को जन्मकंद बनाने की रणनीति अपनाए हुए है। यदि दोनों फाँों के बीच संकट समाप्त नहीं होता, तो संसदीय टकरावका प्रभावित हो सकता है।आर्थिक दृष्टि से वह सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। विदेशी निवेशक केवल आर्थिक अंकड़े ही नहीं देखते, बल्कि वह भी देखते हैं कि किसी देश की संसद कितनी स्थिरता और दक्षता से

इसके लिए कर सुधार, औद्योगिक विस्तार,रोजगार सृजन, शिक्षा, कृषि, डिजिटल प्रशासन और राजनीतिक सक्षमति जैसे अनेक क्षेत्रों में निरंतर सुधार आवश्यक हैं। संसद इन सभी सुधारों का सबसे बड़ा लेकनीकाल का संदेश जा सकता है। साक्षियों, मगरही शैर्य बाजार भी इस सत्र पर निफट टूटि रहे हुए हैं। बैकिंग, कर सुधार, एएसएसईई विनिर्माण डिजिटल अर्थव्यवस्था और आधारभूत संरचना से जुड़े विधेयकों का सीधा प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्रों पर पड़ सकता है। यदि संसद सुकलवादी एजेन्ड आगे बढ़ने में सफल रहती है, तो दीर्घकाल में निवेशकों का विश्वास और मनचूर हो सकता है।अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का यह सत्र महत्वपूर्ण माना जा रहा है।भारत आज भी जी-20 क्रिस कावद तथा वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऐसे में संसद की कार्यक्षमता यह संदेश देती है कि भारत केवल ठेग आर्थिक विकास ही नहीं, बल्कि लेकनीकाल संस्थाओं की मजबूती के साथ भी आगे बढ़ रहा है। हालांकि विदेशी संसदों, बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेशों और वैश्विक कंटेिंग एजेंसीयों भी इस सत्र के परिणामों पर नजर रख रही हैं। साक्षियों, विजन-2047 के संदर्भ में भी यह मासूम सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है।विकसित भारत के लक्ष्य केकेलआर्थिक जुड़ने में प्राप्त नहीं होगा,

सैलून की दुकान में घुसी अनियंत्रित बाइक, दो लोग गंभीर रूप से घायल

नेबुआ नौरंगिया, कुशीनगर। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के सिरसिया पंचायत भवन के सामने एक अनियंत्रित बाइक सैलून की दुकान में घुस गई, जिससे दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सिंगल निवासी नीतीश शाही किसी कार्य से बाइक से जा रहे थे। पंचायत भवन के सामने उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित एक सैलून की दुकान में घुस गई। उस समय शिवभजन चौहान पुत्र रामबली चौहान, निवासी सिरसिया कला, दुकान में एक ग्राहक के बाल काट रहे थे। बाइक की जोरदार टक्कर से शिवभजन चौहान गंभीर रूप से घायल हो गए।

भाजपा का सातों विधानसभा क्षेत्रों में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आज, चुनावी तैयारियों को मिलेगी धार

कुशीनगर।

आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को गति देने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी बुधवार को जनपद की सभी सात विधानसभा क्षेत्रों में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित करेगी। पार्टी ने इसे संगठन सुदृढ़ीकरण और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है। जिला मीडिया प्रभारी अमित राय ने जिलाध्यक्ष दुर्गा राय के हवाले से बताया कि सम्मेलन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खड्डा विधानसभा के 388 बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन अनमोल विवाह पैलेस में होगा, जहां वरिष्ठ भाजपा नेता एवं जिला प्रभारी संत राज यादव मुख्य अतिथि रहेंगे।

पडरौना विधानसभा के 434 बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन पीएम पैलेस, जटहा रोड पर आयोजित होगा, जिसमें क्षेत्रीय महामंत्री सुनील गुप्ता शामिल होंगे। तमकुहीराज विधानसभा के 455 बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सेवरखी में पूर्व जिलाध्यक्ष देवरिया भूपेंद्र सिंह की उपस्थिति में होगा। फाजिलनगर विधानसभा के 472 बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन पाव नगर स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पूर्व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मारकंडे शाही की मौजूदगी में आयोजित किया जाएगा। कुशीनगर विधानसभा के 445 बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन राजधराना मैरिज हॉल, कसया में होगा, जहां क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विश्वजीतांशु सिंह 'आंशु' मुख्य अतिथि रहेंगे। खटा विधानसभा के

420 बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन मंगलम मैरिज हॉल में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉ. सत्येंद्र सिंह की उपस्थिति में तथा रामकोला विधानसभा के 399 बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन समर मैरिज हॉल में पूर्व जिलाध्यक्ष महाराजगंज परदेसी रविदास की मौजूदगी में आयोजित किया जाएगा। पार्टी के अनुसार सम्मेलन में बूथ समितियों की सक्रियता, संगठनात्मक मजबूती और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार सम्मेलन में केवल बूथ अध्यक्ष, विधानसभा क्षेत्र में निवास करने वाले वर्तमान एवं पूर्व क्षेत्रीय पदाधिकारी, पूर्व विधायक, सांसद, संबंधित पूर्व जिलाध्यक्ष तथा वर्तमान जिला पदाधिकारी ही प्रतिभाग करेंगे।

असंगठित श्रमिकों को भूमि अधिकार और कानूनी योजनाओं की दी गई जानकारी, दो दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर सम्पन्न

पडरौना, कुशीनगर। एक्शनएड एसोसिएशन द्वारा संचालित श्रमिक सुविधा केंद्र एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में पडरौना स्थित एक मैरिज हॉल में आयोजित दो दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर का मंगलवार को समापन हो गया। शिविर में जनपद के विभिन्न विकासखंडों से आए 120 असंगठित श्रमिकों को भूमि अधिकार, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर की शुरुआत रामबृक्ष गिरि ने करते हुए कार्यशाला के उद्देश्य एवं विधिक जागरूकता की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। पहले दिन अधिकता जितेंद्र पटेल ने भूमि अधिकार एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधियों ने वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं के अधिकार, महिला सुरक्षा तथा जनसंख्या नियंत्रण से जुड़े कानूनी प्रावधानों और नालसा की योजनाओं पर विस्तार से जानकारी साझा की। दूसरे दिन विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) तथा महिला सशक्तिकरण के लिए संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वक्ताओं ने श्रमिकों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सबनम प्रदिप्ता, धर्मश्रीला, बुद्ध रतन, पवन कुमार, दिलसाद अंसारी तथा श्रमिक सुविधा केंद्र के रघु प्रसाद, दिनेश प्रसाद, रामबहाल सिंह, दुर्गा देवी सहित बड़ी संख्या में श्रमिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

शिशु मन्दिर में हुई वेश प्रतियोगिता, 15 अगस्त को सम्मानित किये गये अखिल आर्य बच्चे



गौराबादशाहपुर, जौनपुर। स्थानीय क्षेत्र में स्थित सरस्वती शिशु मंदिर माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को वेश प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता की निर्णायक सीमा सिंह चौहान एवं चंद्रा गुप्ता रही जिन्होंने निम्नलिखित भैया बहनों का चयन किया। शिशु वर्ग में बहन वामिका मिश्रा, बहन अश्विना सिंह प्रथम, बहन प्रिंसी गुप्ता द्वितीय, बहन आस्था साहू, अनामिका गुप्ता तृतीय आयी। बाल वर्ग में बहन गौरी जायसवाल, रिया यादव प्रथम, बहन श्रेया सिंह, बहन ज्योति प्रजापति, भैया अर्जुन द्वितीय, बहन श्रेयांशी मोदनवाल, भैया तेजल सिंह, भैया अगस्त्या गुप्ता तृतीय आयी। किशोर और तरुण वर्ग में बहन सुष्टि सिंह प्रथम, भैया ओम गुप्ता, बहन फल्लवी सिंह द्वितीय, बहन हिमांशी पाल, भैया अंश मिश्रा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य कमलेश जी ने सभी विजय भैया-बहनों को शुभकामना देते हुये बताया कि इसका पुरस्कार वितरण आगामी 15 अगस्त को किया जायेगा। उक्त अवसर पर तमाम लोग उपस्थित रहे।

जंघई रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना से मचा हड़कम्प

मौरगंज, जौनपुर।

स्थानीय थाना क्षेत्र के जंघई रेलवे स्टेशन पर मंगलवार की सुबह बम होने की सूचना से रेलवे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी), रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और रेलवे प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। स्टेशन परिसर को सुरक्षा घेरे में लेकर चप्पे-चप्पे की तलाशी ली गई। कई घंटे तक चले सघन तलाशी अभियान के बावजूद कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली।

इसके बाद अधिकारियों और यात्रियों ने राहत की सांस ली। पुलिस के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 6:30 बजे एक अज्ञात व्यक्ति ने जीआरपी जंघई को फोन कर सूचना दी कि स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर एक लावारिस ट्रॉली बैग रखा है जिससे बम जैसी आवाज आ रही है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौरगंज, चौकी



प्रभारी जंघई, जीआरपी प्रभारी और आरपीएफ के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल पूरे स्टेशन परिसर की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, फुटओवर ब्रिज, पार्सल कार्यालय, पार्किंग स्थल, प्रवेश एवं नििकास द्वार समेत स्टेशन के हर हिस्से की गहन जांच की गई।

यात्रियों के सामान पर भी विशेष निगरानी रखी गई और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। काफी देर तक चले अभियान के बावजूद कोई

भी संदिग्ध ट्रॉली बैग, विस्फोटक सामग्री अथवा अन्य आपतजनक वस्तु बरामद नहीं हुई। घटना की गंभीरता को देखते हुए आरपीएफ ने प्रयागराज से बम निरोधक दस्ते को भी अलर्ट कर मौके के लिए खाना किया।

सुरक्षा एजेंसियों ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत पूरे स्टेशन परिसर की दोबारा जांच करायी। जांच पूरी होने के बाद स्टेशन को सुरक्षित घोषित कर दिया गया और रेल यातायात सामान्य रूप से संचालित होता रहा। पुलिस जांच में सामने आया कि सूचना देने वाले

सुरक्षा एजेंसियों ने घंटों खंगाला चप्पा-चप्पा मगर नहीं मिला कुछ संदिग्ध

व्यक्ति ने कॉल करने के कुछ ही मिनट बाद अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया। इसके बाद पुलिस संभावित मोबाइल नम्बर की कॉल डिटेल, लोकेशन सहित अन्य तकनीकी साध्यों के आधार पर उसकी पहचान में जुट गई है। प्रथम दृष्टया मामला शरारतन दी गई फर्जी सूचना प्रतीत हो रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रेलवे स्टेशन जैसे संवेदनशील स्थान पर बम की झूठी सूचना देना गंभीर अपराध है। ऐसी सूचना से यात्रियों में अनावश्यक दहशत फैलती है और सुरक्षा एजेंसियों के समय व संसाधनों का भी दुरुपयोग होता है। यदि जांच में सूचना फर्जी साबित होती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर मामले में कोर्ट सख्त, पुलिस से 27 जुलाई तक मांगी प्रगति रिपोर्ट

कार्यवाहक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विवेक सोबरन सिंह से तलब की रिपोर्ट

देवरिया।

पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के खिलाफ सदर कोतवाली में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में पुलिसिया जांच की सुस्त रफ्तार पर न्यायालय ने कड़ा सख्तान लिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवरिया की अदालत ने मामले की विवेचना कर रहे उपनिरीक्षक सोबरन सिंह को आगामी 27 जुलाई तक अब तक की कार्यवाही की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के कड़े निर्देश दिए हैं। अदालत का यह आदेश आरोपी पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता प्रवीण द्विवेदी द्वारा दाखिल प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के बाद आया है। अदालत में प्रस्तुत अर्जी में अधिवक्ता ने पुलिस की कार्यशैली और जांच की गति पर सवाल उठाते हुए कहा कि मामला दर्ज हुए दस महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस अब तक किसी तार्किक निष्कर्ष तक



नहीं पहुंच सकी है। शाहजहांपुर में चलती ट्रेन से आरोपी की गिरफ्तारी और दो माह तक जेल में रहने के बावजूद अंतिम आख्या अदालत के समक्ष प्रस्तुत न करना उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 122 तथा पुलिस मॉडनिजेशन के दिशा-निर्देशों की अवहेलना है। मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, 12 सितंबर 2025 को देवरिया स्थित एक औद्योगिक भूखंड के आवंटन में

कथित अनियमितता और रसूख के दुरुपयोग के आरोपों में अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में 10 दिसंबर को गिरफ्तारी के बाद आरोपी को लगभग दो महीने तक देवरिया कारागार में रखा गया था। अब अदालत द्वारा प्रगति रिपोर्ट तलब किए जाने के बाद पुलिस महकमे में हलचल बढ़ गई है।

अन्त्योदय कार्ड बनाने में धनउगाही का आरोप, कम्प्यूटर ऑपरेटर को हटाने की मांग

दुदही, कुशीनगर। दुदही विकासखंड के मंडरिया गांव की एक महिला ने तमकुहीराज तहसील स्थित आपूर्ति विभाग में कार्यरत एक प्राइवेट कम्प्यूटर ऑपरेटर पर अन्त्योदय राशन कार्ड बनाने के नाम पर धनउगाही का आरोप लगाया है। मामले में उपजिलाधिकारी तमकुहीराज को शिकायती पत्र देकर जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायतकर्ता इसरावती देवी पत्नी गणेश प्रसाद ने उपजिलाधिकारी

आकांक्षा मिश्रा को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह भूमिहीन हैं तथा उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर है। ग्राम पंचायत द्वारा अन्त्योदय कार्ड के लिए प्रस्ताव किए जाने के बाद वह 17 जुलाई को आवश्यक दस्तावेज जमा करने आपूर्ति कार्यालय पहुंची। महिला का आरोप है कि पिछले लगभग 15 वर्षों से कार्यरत प्राइवेट कम्प्यूटर ऑपरेटर कमलेश यादव ने अन्त्योदय कार्ड बनाने के एवज में पाँच हजार रुपये की मांग की। आरोप

है कि रुपये न देने पर उनका काम न करने की बात कही गई। शिकायतकर्ता ने उपजिलाधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच करकर संबंधित ऑपरेटर के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने, उसे हटाने तथा बिना किसी अवैध वसूली के उनका अन्त्योदय कार्ड जारी करने की मांग की है। फिलहाल मामले में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जांच के बाद ही आरोपों की पुष्टि हो सकेगी।

एम्बुलेंस लिखी वैन से 25 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद

कुशीनगर। जनपद में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत तरयासुजान थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस लिखी एक मारुति सुजुकी वैन से 25 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस ने मौके से बिहार निवासी एक तस्कर को गिरफ्तार कर वाहन को भी कब्जे में ले लिया। पुलिस के अनुसार मंगलवार को थाना क्षेत्र में

चेकिंग के दौरान वाहन संख्या BR 32 8926 की मारुति सुजुकी वैन की तलाशी लेने पर उसमें छिपाकर रखी गई ऑफिसर ज्वाइंस ओरिजिनल व्हिस्की की 25 पैटिया बरामद हुईं। प्रत्येक पेटी में 48 पाउच (180 एमएल) थे। बरामद शराब की कुल मात्रा 216 लीटर बताई गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बिक्रम कुमार पुत्र बबलू राय, निवासी बौरपुर, थाना बौरपुर, जनपद

बेगूसराय (बिहार) के रूप में हुई है। बरामदगी के आधार पर थाना तरयासुजान में आबकारी अधिनियम की धारा 60/72 के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई को थानाध्यक्ष नितिन रघुनाथ सिंह के नेतृत्व में उपनिरीक्षक अतुल कुमार बिंद तथा पुलिस टीम ने अंजाम दिया। पुलिस मामले में शराब तस्करों के नेटवर्क की भी जांच कर रही है।



देवरिया।

जनकल्याणकारी योजनाओं को चारदशी तरीके से धरतल पर उतारने और सीधे पात्र व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन

द्वारा शुरू की गई मुहिम रंग ला रही है। मंगलवार को जिलाधिकारी के निर्देश पर रुद्रपुर तहसील सभागार में एक भव्य संयुक्त कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रुद्रपुर के विधायक

जयप्रकाश निषाद ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकात की, जहां उपजिलाधिकारी और जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी प्रियंका चौधरी ने बुके भेंट कर उनका औपचारिक स्वागत किया। शिविर के दौरान विभिन्न प्रशासनिक विभागों के समन्वय से पात्र लाभार्थियों को सीधे लाभान्वित किया गया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आठ दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण और दस को दिव्यांग पेंशन स्वीकृति

दिव्यांगों, वृद्धजनों और छात्राओं को मिले पेंशन व छात्रवृत्ति के प्रमाण पत्र सरकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने पर दिया जोर

पत्र प्रदान किए गए। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से शादी अनुदान के छह लाभार्थियों और छात्रवृत्ति के दस विद्यार्थियों को स्वीकृति पत्र मिले। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने छह छात्राओं को

छात्रवृत्ति पत्र दिए, जबकि समाज कल्याण विभाग ने दस बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन और छह छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृति पत्र सौंपे। वहीं, प्रवेशन विभाग द्वारा तीन महिलाओं को निराश्रित पेंशन योजना से आच्छादित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक जयप्रकाश निषाद ने कहा कि शासन की मंशा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े गरीब, वंचित और जरूरतमंद व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ने की है। उन्होंने अधिकारियों

को निर्देशित किया कि कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार केवल कागजों तक सीमित न रखकर ग्रामीण अंचलों के घर-घर तक पहुंचाया जाए, ताकि कोई भी पात्र नागरिक वंचित न रहे। शिविर में दिव्यांगजन, समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व श्रम विभाग के अधिकारियों ने अपनी विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। अंत में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी प्रियंका चौधरी ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

एमपी में यूसीसी बिल पास: सीएम यादव बोले- ‘अलग-अलग मजहबी तौल कांटा नहीं चलेगा’, सदन में जमकर हुआ हंगामा

भोपाल । मध्यप्रदेश विधानसभा में सभा नार्मल संहिता (यूसीसी) बिल पास हो गया है। इस दौरान हंगामे के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि वो हिंदू की बात करेगा, वहीं राज करेगा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि समानता हमारी संस्कृति का मूल है। भगवान की दुष्ट में सभी एक समान है, वो इसनीं द्वारा बनाए गए कानून में अलग-अलग व्यवस्था क्यों होने चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए। सीएम यादव ने कहा, 'एम से खेम तक, रॉकेट से रॉकेत तक, अमर से एंथोनी और अकबर तक, देश एक सन्निधन से चले।'

उन्होंने दावा किया कि समान नार्मल संहिता लागू होने के बाद मध्यप्रदेश में भेदभाव से मुक्ति मिलेगी और राज्य गोवा, उत्तरखण्ड और असम के बाद इस दिशा में कदम बढ़ाने वाले चौथे राज्य में शामिल होगा। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों के खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के अलग। जनता इनके कभी माफ नहीं करेगी। उनके व्यवस्था के दौरान विपक्ष का हंगामा जारी रहा, लेकिन मुख्यमंत्री ने सरकार का पक्ष विस्तार से सदन के सामने रख रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में अलग-अलग मजहबी तौल कांट्टा नहीं होगा। सब एक ही बाट से चले जाएंगे। इस दौरान सीएम ने

विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष बतार कि हम अपने दो बेटों को अलग-अलग दुर्लक्षण से क्यों देखते हैं? समान नार्मल संहिता विधेयक पर सदन में वक्तव्य देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को सुबख देने के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दुर्लक्षण और मुस्लिम वोट बैंक की रणनीति करती रही है तब देश को जनता को पोट में खंजर घोंपने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के बाद मध्य प्रदेश में भेदभाव से मुक्ति मिलेगी। उत्तरखंड, गुजरात और असम के बाद अब मध्य प्रदेश में भी समान नार्मल संहिता लागू होने जा रही है। मुख्यमंत्री ने



कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेसियों के 'दांत खाने के और, दिखाने के और है।' अब कांग्रेस का पाखंड और दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस बचा

सकत डॉ. भीमराव अंबेडकर के स्वरूपान का स्तीपर भी सम्मान करती है तो उसे इस विधेयक का सम्मान करना चाहिए। उनका आरोप था कि कांग्रेस वोट बैंक की रणनीति करती

हूए हिंदू-मुस्लिम के नजरिए से काम करती रहे है। मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान कांग्रेस विधायक "चंदा जोरी" और "गद्दी छोड़ें" के नारे लगाते रहे। डॉ. यादव ने दावा किया कि प्रदेश के 93 प्रतिशत नागरिकों ने समान नार्मल संहिता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच ऐसी है कि वह सीधे बात भी लिखी नजर से देखती है। इसी संदर्भ में उन्होंने "जाबो खो भयान नैसो, प्रभु मूत देखो तिन ऐसी" चौपाई का उल्लेख करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के नागरिकों के समानिक और धार्मिक संस्कार पहले की तरह जारी रहेंगे। हालांकि, प्रदेश में होने वाले सभी

किवाले का शासकीय पंजीयन अनिवार्य होगा। पंजीयन नहीं करने पर जुर्माने का प्रचणन किया गया है। उन्होंने कहा कि एक पत्नी के खते हुए दूसरा रिवाज और एक पति के खते हुए दूसरा रिवाज करने की अनुमति नहीं होगी। कांग्रेस के लफ्फार हंगामे के बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि वह विधेयक महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समरसता और सामाजिक समरसता का कानून है तब सभी दलों से इसका समर्थन करने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था, लेकिन भोपाल को तत्काल आजाद घोषित नहीं किया गया था और उसे पाकिस्तान से मिलाने की कोशिश की गई थी। ऐसे लोगों को

'दुब मरवा चाहिए।' मुख्यमंत्री के वक्तव्य के बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधायक आरिफ मसूद से कहा कि यदि वे अपने संबोधन पर चर्चा चाहते हैं तो अपनी सीट पर जाकर अपनी बात रखें। इसके बाद आरिफ मसूद का संबोधन प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। कांग्रेस के हंगामे और विरोध के बीच समान नार्मल संहिता (संशोधन) विधेयक सदन में पारित घोषित कर दिया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश राजधानी (संशोधन) विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। वहीं, विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी।

मैदान में उतरे केजरीवाल: पहले अस्पताल फिर पहुंचे पुलिस स्टेशन, बोले- 80 छात्रों को छुड़ाया



नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल मंगलवार को अपरातल में छात्रों से मिले और शिष्टासत में लिए गए युवाओं को थानों से छुड़ाने पहुंचे। केजरीवाल ने दावा किया कि उन्होंने अलग-अलग थानों से गिरफ्तार किए 70 से 80 लोगों को छुड़वाया। इसके बाद उन्होंने जंतर मंतर जाकर अपने पर बैठे युवाओं से मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सांसद रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सोहन भारद्वाज और विधानसभा में

नेता प्रतिपक्ष अरविश्री के साथ आरएमएल अस्पताल पहुंचे। केजरीवाल ने कहा कि कई घायल बच्चों और पुलिस वालों को यहां आरएमएल अस्पताल में लाया गया था। अस्पताल की ओर से उन्हें बताया गया है कि एक बच्ची को छोड़कर बाकी सभी घायल बच्चे और पुलिस वाले डिस्चार्ज हो चुके हैं। बच्ची आईसीयू में है। उन्होंने बच्ची के परिवार से मिलकर उसके कुशलचयम की प्रार्थना की। दो धाने पहुंचे केजरीवाल इसके बाद केजरीवाल मंदिर मार्ग थाने और संसद मार्ग थाने पहुंचे। उन्होंने बताया कि मंदिर मार्ग थाने में सोमवार से लगभग 11 बच्चों को हिरासत में रखा हुआ है। उन्होंने पुलिस से युवाओं को हिरासत में रखे जाने, छोड़ने या उन पर एफआईआर करके गिरफ्तार करने की बात पूछी। पुलिस ने उनसे दो घंटे में जानकारी देने की कहा। आप का दावा: 70-80 छात्रों को छुड़ाया उन्होंने दावा किया कि सुबह से उन्होंने अलग-अलग थानों में गिरफ्तार कर रखे गए 70 से 80 लोगों छुड़वाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के इशारे पर पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया, अंमू गैस के गोले छोड़े और पत्थर बरसाए। उन्होंने कहा कि अब शिक्षा मंत्री धर्मंद प्रधान का नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। उन्होंने नाग दिया कि मोदी हटाओ-देश बचाओ।

दिल्ली-एनसीआर में तीन दिन बारिश



नई दिल्ली । दिल्ली में सोमवार देर रात शुरू हुई बारिश मंगलवार को भी जारी रही। इसके चलते राजधानी के तापमान में मामूली से तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, इस बारिश ने कई इलाकों में जलभराव और लंबा यातायात जाम भी पैदा किया, जिससे लोगों को परेशानी हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, पिछले 24 घंटों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में यह गिरावट आई है। मंगलवार को सफरदर्जन मान केंद्र में अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री और

इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार, सुबह 8:30 से 11:30 बजे के बीच सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई। इस दौरान अथा नगर में सर्वाधिक 11.9 मिमी बारिश हुई। फलम में 8.8 मिमी और उत्तरपुर में श्रात मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। अन्य इलाकों में भी हल्की बारिश हुई, जैसे जाफरपुर में 4.5 मिमी और जन्कपुरी में पांच मिमी। मौसम विभाग ने 22 से 27 जुलाई तक दिल्ली में सामान्यतः बादलों से ढिंरा मौसम रहने का अनुमान बताया है। 22 जुलाई को सुबह से दोपहर के बीच कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और तेज हवाएं चलेंगी। 23 और 24 जुलाई को भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के असर है। वहीं, 25 से 27 जुलाई तक बारिश की संभावना नहीं है, हालांकि आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 से 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

राज खुलने के डर से नहीं हो रहा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा- अखिलेश यादव



नई दिल्ली । समाजवादी पार्टी के प्रमुख और लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने मंगलवार को केंद्र सरकार को आलोचना की। उन्होंने फेर लोक के कथित मामले और राजधानी में छत्रक के विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और कहा कि परिश्रमों की खुर्चिा बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। संसद में पत्रकारों से बात करते हुए यादव ने कहा कि सरकार फेर लोक एकाने में नाकाम रही है और उन्होंने सततपरी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने सोमवार के विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि छात्रों पर बहुत बुराई बल प्रयोग किया गया। यादव ने कहा, यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि फेर लोक न हो। इसी बड़ी गड़बड़ी के बाद भी सदन में नारे लग रहे हैं। इसी ज्ञात शर्मनाक और क्या हो सकता है? सरकार को लाइश्रों से

सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल ले जाने का दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश



नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की नईपैठ ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफरदर्जन अस्पताल से मेदांता अस्पताल, गुवागम स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। उसने पत्नी डॉ. गौतमजलि अंग्मो की अपील पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस

कांरिख को पोट ने चिकित्सकीय रिपोर्ट्स की समीक्षा के बाद कहा कि वांगचुक को निरंतर और सतत चिकित्सकीय निगरानी की आवश्यकता है। कोर्ट ने मेदांता अस्पताल के निदेशक को विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम तद्वित करने का निर्देश दिया, जो उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी करेंगे और स्वीकृत चिकित्सा मानकों के अनुसार उपचार प्रदान करेंगे। सुनवाई के दौरान सखींसिंह जनखल ने केंद्र सरकार की ओर से कई आरोपित नहीं जताई। कोर्ट ने सफरदर्जन अस्पताल के सभी मैडिकल रिकॉर्ड तुरंत मेदांता को सीएम की कहा। साथ ही, गौतमजलि अंग्मो को पति से मिलने की पूरी छूट दी गई है।

जखरत पड़ी तो सीजेपी के आंदोलन में शामिल होने दिल्ली जाऊंगी- ममता

गुगमल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी ने दिल्ली में सीजेपी के संसद मार्च के दौरान छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जखरत पड़ी तो वह सीजेपी के आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली जाएंगी। मंगलवार को कोलकाता में टीएमसी की वार्षिक 21 जुलाई शहद दिवस रैली को संबोधित करते हुए ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेता केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों को दसाने का आरोप लगाया। ममता ने मंगलवार को दिल्ली में हुई झड़पों का जिक्र करते हुए कहा, अगर जखरत पड़ी तो मैं दिल्ली जाऊंगी और सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल होऊंगी। उन्होंने

दावा किया कि प्रदर्शनकारी जन संसद परिसर के करीब पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कार भुग ली और वहां से चले गए। हालांकि, ममता ने इस दावे के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने छात्रों के आंदोलन के खिलाफ कार्रवाई कर लोकतंत्र के प्रति असहिष्णुता दिखाई है। ममता ने आरोप लगाया कि सरकार पूछने वाले छात्रों को संवाद के बजाय लाठी और अंमू गैस का समाना करना पड़ रहा है। उन्होंने भाजपा सरकार पर तनाशाही की हदें पार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। ममता ने कॉविड-19 महामारी के दौरान कथित खरीद अनियमितताओं की जांच की लेकर भी केंद्र और



पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री शुभेंद्र आंध्रप्रदेश ने सोमवार को 1993 के पुलिस गेंतोकांड की लॉक जांच रिपोर्ट जारी की। ममता ने कॉविड-19 महामारी के अफ्फान रहत वितरण और कॉविड काल में चिकित्सा उपकरणों की

भेदभाव का आरोप लगाया। ममता ने कहा कि योग दिवस कार्यक्रम के लिए रैड रोड को सात दिनों तक बंद रखा गया, लेकिन ककरौद पर मजान की अमूर्ति नहीं दी गई। सीजेपी का आंदोलन कथित परीक्षा अनियमितताओं और फेर लोक के विरोध से शुरू हुआ था। सीएम वांगचुक की भूल हड़ताल के बाद प्रदर्शन तेज हुआ। प्रदर्शनकारी वांगचुक को रिहाई, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मंद प्रधान के इस्तीफे और कथित अशान्दता करने वाले एफआईटी अर्थव्यर्थियों के परिजनों को एक करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। सोमवार को संसद मार्च के दौरान हुई झड़पों में 118 से अधिक पुलिसकर्मी और करीब 60 प्रदर्शनकारी घायल हुए।

खितिकम की निर्माणधीन टनल पर लैंडरलाइड, 10 मजदूरों की मौत:17 अब भी फंसे

गंगटोक । सिक्किम में सोमवार को एक टनल पर लैंडरलाइड होने से उसका 10 गेट बंद हो गया, जिससे अंदर मौजूद 27 मजदूर फंस गए। इनमें से 10 की मौत हो गई। मुक्तों में 3 की जानकारी अभी नहीं हो पाई है, जबकि 17 मजदूर अब भी फंसे हैं। नामची किले के मार्गीर स्थित समारुदा सुरंग में निर्माण कार्य चल रहा था। एसपी सोनम खेल्या ने बताया कि फंसे हुए मजदूरों की संख्या 27 से कम या ज्यादा भी हो सकती है। सुरंग में मोहन गैस लीक होने की आशंका है। कई बचावकार्मियों को अंदर जाने के दौरान जखरत आए।



राहुल गांधी के प्रदर्शन पर क्या बोले धर्मंद प्रधान?



लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को पौराण अजय के पास कांग्रेस समेत विपक्ष के नेताओं के साथ प्रदर्शन किया। इस पर शिक्षा मंत्री धर्मंद प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी छात्रों का फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने सरकार की जवाबदेही की तरफ समेत करते हुए कहा, हमें युवाओं और छात्रों के लिए इनके गुस्से से कहीं अधिक करने की जरूरत है। प्रधान का बयान ऐसे समय में सामने आया है जब दिल्ली में कार्यकारी जनश्र पार्टी और कांग्रेस पार्टी समेत कई दलों के नेता और प्रतिनिधि परीक्षा के अत्यधिक सड़कों पर उतर आए हैं।

राहुल को धरने से पुलिस उठाकर ले गई, 3 घंटे बाद छोड़ा

हिरासत में विपक्षी नेता: राहुल सड़क पर लेट गए, अखिलेश बोले- ‘पुलिस भैया, कहां लेकर जा रहे हो?’

नई दिल्ली । कार्योच जनता पार्टी (सीजेपी) के जंतर-मंतर से संसद तक मार्च निकालने की कोशिश और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मंगलवार को कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा के कई सांसद अजानक प्रधानमंत्री आवास, 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। कांग्रेस नेताओं ने छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज का विरोध करते हुए नीट पेर लोक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मंद प्रधान के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया। इसके



कहते सुनाई देते हैं, 'पुलिस भैया, कहां लेकर जा रहे हो?' इस पूरे घटनाक्रम पर राहुल गांधी ने मोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, 'कल युवा छात्रों के साथ हुई बबरता के लिए प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांगने के लिए हम उनके घर तक पैदल मार्च करके गए। सरकार न तो कोई जवाबदेही लेना चाहती है और न ही संसद में इस पर बहस करना चाहती है। भारत के युवाओं के भविष्य को बचाद करने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।'

प्रियंका गांधी को भी हिरासत में लिया गया दिल्ली पुलिस ने वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी को भी हिरासत में ले लिया है। हिरासत में

प्रियंका गांधी बोलीं- शिक्षा व्यवस्था को सुधारना होगा, धर्मंद प्रधान दें इस्तीफा



कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाझा ने मंगलवार को मंत्री मार्ग थाने से रिहा होने के बाद केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मंद प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। देश के मुद्दे और छात्रों की मांगों के सम्बंध में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया था। रिहाई के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि छात्रों की मांगें पूरी तरह जायज हैं और लोकतंत्र में विरोध-प्रदर्शन करना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा, 'देश के बच्चों, जो हमारे देश का भविष्य हैं, उनकी बात सुनने में क्या दिक्कत है? उनकी मांग बिचल जायज है। उनके प्रतिनिधि होने के नाते उनकी आवाज उठाना और उन्हें मनचुली देना हमारी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में विरोध-प्रदर्शन करना एक मौलिक अधिकार है। जहां भी जरूरत होगी, हम अपनी अजबन उठाएंगे। हमारी मांग शुरू से ही स्पष्ट है। हमें दृढ़ी हुई शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना होगा।' प्रियंका गांधी ने कहा, 'धर्मंद प्रधान को इस्तीफा देना होगा। संसद में इस मुद्दे पर चर्चा होने चाहिए और छात्रों की बात सुनी जानी चाहिए। 'बंद मास' का क्या मतलब है? अपनी मातृभूमि का सम्मान करना। हमारी मातृभूमि लोकतंत्र है। ये बच्चे कौन हैं? यही वे लोग हैं जिन्होंने हमें संसद में भेजा है। शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए विधेयक क्यों नहीं लाया जाता? अजनी-अजनी के 16 लाख करोड़ रुपये के कर्ज माफ कर दिए गए, लेकिन पूरे देश की शिक्षा पर सिर्फ 1.4 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए।'



सक्षम भारत की बेवसाईड से जुड़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें।

छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर संसद में विपक्ष हमलावर, कांग्रेस सांसदों ने शाह से मांगा जवाब

नई दिल्ली । संसद के मामूनु सत्र के दौरान मंगलवार को कांग्रेस के सांसदों ने केंद्र सरकार की अक्रोचना की है। उन्होंने यह उल्लेखन दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज, अंमू गैस के इस्तेमाल और पुलिस कार्रवाई को लेकर की है। पार्टी नेताओं ने संसद में इस पूरे मामले पर चर्चा

कामे और गृह मंत्री अमित शाह से दोनों सदनों में विस्तृत बयान देने की मांग की। कक्षीय सांसद शशि धरु ने फंसकों से बात करते हुए कहा कि देश और राजधानी से जुड़े कई गंभीर मुद्दे संसद के सामने हैं, जिन पर चर्चा होना आवश्यक है। अगर संसद ऐसी

महत्वपूर्ण विषयों पर बहस का मंच नहीं बनेगी, तो फिर चर्चा कहां होगी। धरु ने लोकसभा अध्यक्ष से हस्तक्षेप कर संसद में जरी गौरव्य समाज कराने और छात्रों के विरोध प्रदर्शन, भूख हड़ताल, पुलिस कार्रवाई और हिंसा सहित पूरे घटनाक्रम पर खुली चर्चा कराने की अपील की। उन्होंने

कहा कि इस घटना में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए और करीब 100 लोगों को राम मन्तर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवा पड़ा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने संसद को कार्यवाही को अग्रगण्य बताया और आरोप लगाया कि सफरदर्जन के संसदों ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरी

को बोलने से रोक। उनके अनुसार, खरी दिल्ली में छात्रों के खिलाफ हुई कथित हिंसा का मुद्दा उठाना चाहते थे। कक्षीय की मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह संसद के दोनों सदनों में उपस्थित रहकर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर स्पष्टीकरण दें। इसके साथ ही छात्रों से जुड़े लगातार पेर लोक के मामले,

युवाओं की आश्रयता और परीक्षा व्यवस्था में बिचल के संकेत जैसे मुद्दों पर भी गंभीर चर्चा होनी चाहिए। कक्षीय सांसद प्रणति शिंदे ने कहा कि प्रदर्शन शान्तिपूर्ण था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, अंमू गैस का इस्तेमाल हुआ।